



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]
No. 485]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1990/कार्तिक 12, 1912
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1990/KARTIKA 12, 1912

इस भाग में खिल पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे इक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कल्याण मंत्रालय

(कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1990

सा. का. नि. 891 (ई).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की गति और पवारिति) नियम, 1990 है।

(2) ये संविधान (पैंचवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ की तरीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संवर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

- (ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) "आयोग" से अनुच्छेद 338 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं;
- (ङ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" पदों के वहीं अर्थ हैं जो अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं;
- (च) "उपाध्यक्ष" से आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. अहंताएँ :—(1) सदस्यों की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हैं,—

- (क) अध्यक्ष की नियुक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे प्रतिष्ठित सामाजिक-

- (राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से की जाएगी जो अपने व्यक्तित्व और निःस्वार्थ सेवा के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच विश्वास पैदा करते हैं;
- (ख) उपाध्यक्ष और तीन से अन्यून अन्य सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे;
- (ग) कम से कम एक अन्य सदस्य महिलाओं में से नियुक्त किया जाएगा।

4. सदस्यों की नियुक्ति:—इन नियमों के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्य अंशकालिक अधिकार पर भी नियुक्त किए जा सकेंगे।

5. पदावधि:—(1) इन नियमों में जैसा अन्यथा उल्लिखित है उसके सिवाय, प्रत्येक सदस्य ऐसी तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है, तो उस वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परन्तु प्रथम अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

6. पद का चक्रानुक्रम:—अध्यक्ष की तीन पदावधियों के ब्लाक में, अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अध्यक्ष का पद को पदावधियों के लिए धारण करेगा और अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति अध्यक्ष का पद एक पदावधि के लिए धारण करेगा।

परन्तु जहाँ अध्यक्ष अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से है वहाँ उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से होगा और जहाँ अध्यक्ष अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से है वहाँ उपाध्यक्ष अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से होगा।

7. वेतन और भत्ते:—(1) जब तक कि अन्यथा विनिदिष्ट न किया जाए, प्रत्येक सदस्य भारत सरकार के सचिव के रैंक का होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं;

परन्तु अध्यक्ष किसायामक ग्राहकार्य के भी हकदार होंगे।

(3) उपनियम (1), उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल का सदस्य है तो वह संसद् (निरहेता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित भत्ते से भिन्न या, यथास्थिति, ऐसे भत्तों से भिन्न यदि कोई हों, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा जो राज्य के विधान-मंडल का

कोई सदस्य, राज्य विधान-मंडल की सदस्यता के लिए निरहेता के निवारण के संबंध में राज्य में तत्त्वमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी निरहेता उपगत किए विना प्राप्त कर सकेगा।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया कोई सदस्य ऐसे यात्रा भत्तों और ईमिल भत्तों का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव की दशा में नागू होते हैं।

8. स्थायी या अस्थायी रिक्तियों की दशा में प्रबंधः—

(1) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, या यदि ग्राहक विधि किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में अमर्दय है तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं करता है या विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(2) यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, या यदि उपाध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में अमर्दय है तो उन कर्तव्यों का ऐसे अन्य सदस्य द्वारा, जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं करता है या विद्यमान उपाध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

9. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त मेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबन्धः—

जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है अथवा कोई सेवानिवृत्त सरकारी भेवक है अथवा किसी अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त सेवक है और किसी पूर्वांकी सेवा की वावत पैशान प्राप्त कर रहा है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य नियुक्त किया जाता है वहाँ इन नियमों के अधीन उस अनुज्ञेय वेतन में से उस पैशान की रकम और यदि उसने पैशान के किसी भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो, पैशान के उस भाग की रकम कम कर दी जाएगी।

10. पदव्याप और हटाया जाना:—(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) (क) अध्यक्ष को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्वेश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (अ) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया गया।

है कि अध्यक्ष को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए;

(ब) राष्ट्रपति, अध्यक्ष को, जिसके संबंध में इस उपनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्वेश किया गया है, उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्वेश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन प्रियते पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है;

(ग) खंड (क) में किसी भात के होते हुए भी यदि अध्यक्षः—

- (i) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या
- (ii) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी भवेतन नियोजन में लगता है; या
- (iii) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैक्षिलय के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; तो राष्ट्रपति अध्यक्ष को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष को इस खंड के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(घ) यदि अध्यक्ष, नियमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या नियमित की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपूर्ण या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उसमें उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो वह खंड (क) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

(3) राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष या सदस्य के पद में तभी हटाएगा जब वह व्यक्ति,—

- (क) अनुमोदित दिवालिया है;
- (ख) किसी अपराध के लिए जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्भूत है, सिद्धांश ठहराया जाता है और कागवास में दंडादिष्ट किया जाता है;
- (ग) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक शैक्षिलय के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है;
- (घ) कार्य करने में इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ है;
- (ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिए थिन्, आयोग की तीन अमर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए हानिकारक होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

[सं. 13012/2/90 एस.सी.डी.-VI]
टि. मुनिवेकटप्पा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

(Department of Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1990

G.S.R. 891(E):—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 338 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 1990.
- (2) They shall come into force on the date of commencement of the Constitution (Sixty-fifth Amendment) Act, 1990.
2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires :—
 - (a) “article” means article of the Constitution;
 - (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Commission;
 - (c) “Commission” means the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes established under article 338;
 - (d) “Member” means a Member of the Commission and includes the Chairperson and the Vice-Chairperson;
 - (e) the expressions “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366;

(f) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Commission.

3. Qualifications:—(1) The Members shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have had a record of selfless service to the cause of justice for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1):—

- (a) the Chairperson shall be appointed from amongst eminent socio-political workers belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, who inspire confidence amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by their very personality and record of selfless service;
- (b) the Vice-Chairperson and not less than three other Members shall be appointed from amongst persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (c) at least one other Member shall be appointed from amongst women.

4. Appointment of Members:—The Members to be appointed under these Rules may be appointed on part-time basis also.

5. Term of Office:—Save as otherwise provided in these Rules, every Member shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes such office :

Provided that the first Chairperson shall hold office for a term of five years from the date of his assumption of office.

6. Rotation of Office:—In a block of three terms of Office of the Chairperson, a person belonging to the Scheduled Castes shall hold office of the Chairperson for two terms and a person belonging to the Scheduled Tribes shall hold office of the Chairperson for one term:

Provided that where the Chairperson is from amongst persons belonging to the Scheduled Castes, the Vice-Chairperson shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Tribes and where the Chairperson is from amongst persons belonging to the Scheduled Tribes, the Vice-Chairperson shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes.

7. Salaries and allowances :—(1) Every Member shall have the rank of the Secretary to Government of India unless otherwise specified.

(2) Every Member shall be entitled to such salary, allowances and other facilities as admissible to the Secretary to Government of India:

Provided that the Chairperson shall also be entitled to a rent free accommodation.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), if the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member is a Member of Parliament, or a State Legislature, he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which a Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for Membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification .

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), a Member appointed on part-time basis shall be entitled to travelling allowance and daily allowance applicable to the Secretary to Government of India.

8. Arrangement in case of permanent or temporary vacancies: (1) If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairperson.

(2) If the office of the Vice-Chairperson becomes vacant or if the Vice-Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Vice-Chairperson assumes office or the existing Vice-Chairperson resumes his office, be discharged by such other Member as the President may direct.

9. Special provision for retired persons appointed as Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission;

Where any person, being a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court or a retired government servant or retired servant of any other institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as a Chairperson, Vice-Chairperson or a Member, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he had received in lieu of a portion of the pension the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

10. Resignation and Removal—(1) The Chairperson and Vice-Chairperson and any other Member, may, by notice in writing under his hand addressed to President, resign his post.

(2) (a) The Chairperson shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed by in sub-clause (j) of clause (1) of article 145 of the Constitution, reported that the Chairperson ought on any such ground to be removed.

(b) The President may suspend from office the Chairperson in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under this sub-rule until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(c) Notwithstanding anything in clause (a) the President may by order remove from office the Chairperson if the Chairperson,

- (i) is adjudged an insolvent; or
- (ii) engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
- (iii) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body :

Provided that the Chairperson shall not be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(d) If the Chairperson is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the Government of a State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of clause (a), be deemed to be guilty of misbehaviour.

(3) The President shall remove a person from the office of Vice-Chairperson or Member if that person,—

- (a) becomes an undischarged insolvent;
- (b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude;
- (c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body;
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
- (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or
- (f) in the opinion of the President, has so abused the position of Vice-Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the Scheduled Castes [or Scheduled Tribes;

Provided that no person shall be removed under this sub-rule until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

[F. No. 13012/2/90-SCD.VI]
T. MUNIVENKATAPPA, Jt. Secy.

